



नई दिल्ली, शनिवार
22 मार्च 2025

नई दिल्ली। (राष्ट्रीय संस्करण)

नेशनल प्रेस टाइम्स



राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

वर्ष : 11, अंक : 22

www.nationalpresstimes.com

पृष्ठ : 10

गूण्ड : 05 लप्पा

RNI No : UPHIN/2015/64579

अमेरिका में बंद होगा शिक्षा मंत्रालय: ट्रंप के फैसले के बाद कैसे चलेंगे शिक्षण संस्थान, कौन उठाएगा खर्च?

नई दिल्ली। अमेरिका के शिक्षा मंत्रालय को बंद करने के फैसले के बाद वहां शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी? इस फैसले का देश में शिक्षण संस्थानों पर क्या असर होगा? उनके खर्च कैसे चलेंगे? छात्रों और उनके अभिभावकों का क्या होगा? आइये जानते हैं...

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान शिक्षा मंत्रालय को बंद करने के फैसले के बाद वहां शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी? इस फैसले का देश में शिक्षण संस्थानों पर क्या असर होगा? उनके खर्च कैसे चलेंगे? छात्रों और उनके अभिभावकों का क्या होगा? आइये जानते हैं...

पिछले जाने- क्या है अमेरिका का शिक्षा मंत्रालय, यह करता क्या है?

अमेरिका में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना



मानी जाती है। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। मसलन शिक्षा मंत्रालय को बंद करने के फैसले के बाद अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी? इस फैसले का देश में शिक्षण संस्थानों पर क्या असर होगा? उनके खर्च कैसे चलेंगे? छात्रों और उनके अभिभावकों का क्या होगा? आइये जानते हैं।

ट्रंप के इस फैसले की पूरी दुनिया में चर्चा है। दरअसल, अमेरिका में शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतरीन स्तर की खात्र किया जाना है।

पिछले जाने- क्या है अमेरिका का शिक्षा मंत्रालय, यह करता क्या है?

अमेरिका में शिक्षा मंत्रालय की स्थापना

औरंगजेब का कब्र हटाने की मांग, बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका



नागपुर। पुलिस ने नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान और पांच अन्य के खिलाफ देशद्रोह और सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि हिंसा के तीन दिन बाद शहर के कुछ हिस्सों में कफ्फू हटा लिया गया या उसमें ढील दी गई।

नागपुर हिंसा के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने का मुद्दा हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में

शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (ओआईएल) दायर की गई है। केतन तिरोड़कर नामक व्यक्ति ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर औरंगजेब के मकबरे को ध्वस्त करने तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को औरंगजेब के मकबरे को उत्तर प्रदेश का बताने पर संकोच करते थे पर अब वो गर्व से खुद को उत्तर प्रदेश का नागरिक बताते हैं। सीएम योगी शुक्रवार को अयोध्या के राजसन दो योगी आदित्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में नए नेतृत्व के साथ ही अब दुनिया नये भारत की बात करने लगी है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक दशक पहले की ही बात है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में नए नेतृत्व के साथ ही अब दुनिया नये भारत की बात करने लगी है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक दशक पहले की ही बात है।

उत्तर प्रदेश और भारत के लोग दुनिया में कहीं जाते थे तो खुद को भारतीय कहने पर थोड़ा संकोच करते थे पर अब गर्व से खुद को भारतीय कहते हैं क्योंकि दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। इसी तरह योगी के लोग कहीं बाहर जाने पर खुद को उत्तर प्रदेश का बताने पर संकोच करते थे पर अब वो गर्व से खुद को उत्तर प्रदेश का नागरिक बताते हैं। सीएम योगी शुक्रवार को अयोध्या के राजसन में दो

कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

जेज यशवंत वर्मा के ट्रांसफर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का विरोध

हम कोई कूड़ादान नहीं



इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव विकांत पांडे ने कहा कि यशवंत वर्मा पर आरोप लगाया गया है। उनके घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है, यह हमें मीडिया से पता चला है। बार किसी भी कीमत पर उन्हें यहां स्वीकार नहीं करेगा। हमने 24 मार्च को दोपहर 1 बजे एक आम सभा बुलाई है, जिसमें हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाकी वकीलों से बात करेंगे और हम इसका कड़ा विरोध करने का रहे हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने हाल ही में नकदी स्थोर विवाद के सिलसिले में दिल्ली उच्च

रुप से जुड़ी बड़ी मात्रा में नकदी की खोज से जुड़े विवाद किया है। बार एसोसिएशन ने एक तीखा विवाद जारी करते हुए कहा, "हम कोई कचरा पात्र नहीं हैं," जो इस बात पर गहरा असंतोष दर्शाता है कि यह निर्णय अनुचित है। यह कदम न्यायिक भ्रष्टाचार से कथित

शेष पेज 2 पर

कर्नाटक विधानसभा में बवाल 18 विधायक छह महीने के लिए निलंबित

मार्शलों ने टांगकर बाहर किया

बंगलूरू। कर्नाटक विधानसभा में आज की कार्रवाई हंगामे की भेट चढ़ गई। दिन भर ही ट्रैप और मुसलमान ठेकेदारों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे हंगामा होता रहा। इस दौरान भाजपा विधायकों ने जमकर नरेबाजी की ओर कुछ विधायकों ने अपने हाथों में सीड़ी थामे हुई थी, जिन्हें लेकर दावा किया गया कि उनके पास ही ट्रैप को लेकर स्कूलों को वित्तीय मदद देना था।

अमेरिका में शिक्षा व्यवस्था को चलाने का तरीका, भारत या अन्य देशों के मुकाबले काफी अलग है। अमेरिका में शिक्षा का अधिकतम भार के द्वारा या संघ की सरकार के पास नहीं, बल्कि राज्य और जिला प्रशासन के ऊपर होता है।

शेष पेज 2 पर



जिसके बाद मार्शलों ने उन्हें

की बल्कि अनुशासनहीन तथा जबरन सदन से बाहर निकाला। इसलिए हुई कार्यवाही-कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने यह कार्रवाई विधानसभा की कार्यवाही में वादा डालने वाले विधायकों के खिलाफ की। आरोप है कि विधानसभा में हंगामा कर रहे भाजपा विधायकों ने न सिर्फ अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना

शेष पेज 2 पर

छह महीने के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया।

अब ये काम नहीं कर पाएंगे भाजपा विधायक-निलंबन आदेश के अनुसार, अगले छह महीनों के लिए इन सदस्यों को विधानसभा हॉल, लार्जी और गैलरी में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। उन्हें किसी भी स्थायी समिति की बैठक में भाग लेने और विधानसभा के एजेंडे में अपने नाम से कोई विषय या मामला सूचीबद्ध करने से भी रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, निलंबन अवधि के दौरान उनके द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। न ही उन्हें चुनावों में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान उन्हें कोई दैनिक भत्ता भी नहीं मिलेगा।

शेष पेज 2 पर

अयोध्या में बोले सीएम योगी

एक दशक पहले दुनिया में खुद को मार्टीय कहने में संकोच करते थे लोग



उन्होंने कहा कि मैं एक बार यूरोप गया था और वहां पर भूमने निकला और एक टैक्सी पर बैठा। मुझे टैक्सी वाला भारत का निवासी लगा। मैंने पूछा कि कहा के हो तो उसने कहा पंजाब का। मैंने पूछा पंजाब में कहां से तो चुप हो गया... फिर बताया कि पांक्षिस्तान से हैं। उसने मुझे बताया कि भारत का बताने पर हम यहां पर सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत की ताकत है।

युवाओं को वितरित किया 47 करोड़ का ऋण

यहां से मुख्यमंत्री योगी रामकथा पार्क

शेष पेज 2 पर

'किसी भी तरह की बिलाई बर्दाश्त नहीं': मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा एक्शन, एजीव्यूटिव इंजीनियर को किया स्टैपेंड

नई दिल्ली। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने एजीव्यूटिव इंजीनियर को स्टैपेंड कर दिया है। सभी अधिकारियों को साफ किया। उन्होंने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में नालों और वैटीक से काम नहीं कर

जज के घर कैथ नहीं.. सिर्फ धुआँ!: दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश बेदाग, दमकल विभाग के प्रमुख ने दी जानकारी



नेशनल प्रेस टाइम्स ब्लूरो

नई दिल्ली। डीएफएस प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के आवास पर आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में लगी थी।

दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर आग बुझाने के दौरान अग्निशमन कर्मियों को कोई नकदी नहीं मिली। गर्ग ने पीटीआई को बताया कि 14 मार्च को रात 11.35 बजे नियंत्रण कक्ष को यशवंत वर्मा के लुटियन दिल्ली आवास पर आग लगने की सूचना मिली और दो दमकल गाड़ियां तुरंत मोक्ष पर पहुंच गईं।

दमकल गाड़ियां रात 11.43 बजे मौके पर पहुंचीं। गर्ग ने बताया कि आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में लगी थी। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने में 15 मिनट लगे। कोई हताहत नहीं हुआ। डीएफएस प्रमुख ने कहा कि आग बुझाने के तुरंत बाद हमने पुलिस को आग

की घटना की सूचना दी। इसके बाद दमकल कर्मियों की एक टीम मोक्ष पर चली गई। दमकल कर्मियों को आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वर्मा के खिलाफ शुरूआती जांच शुरू की, जिनके सरकारी आवास से कथित तौर पर आग की घटना के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। कथित तौर पर उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की भी मांग की।

कौन हैं जस्टिस यशवंत वर्मा?

जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बी.कॉम (ऑनर्स) की पढ़ाई की और मध्य प्रेस के रीवा विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. की डिग्री हासिल की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में उन्होंने कॉर्पोरेट कानूनों, कराधान और कानून की संबद्ध शाखाओं के अलावा संवैधानिक, श्रम और औद्योगिक विधानों के मामलों में भी वकालत की।

2016 में स्थायी न्यायाधीश के रूप में ली शपथ 56 वर्षीय न्यायाधीश, जो 1992 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थे, उन्हें 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उन्होंने 1 फरवरी 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

कई पदों पर रहे वह 2006 से अपनी पदोन्ति तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विशेष अधिवक्ता भी रहे, इसके अलावा 2012 से अगस्त 2013 तक उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता भी रहे, जब उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया।

कौन हैं जस्टिस यशवंत वर्मा?

ट्रक चालक, मालिक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिला



नेशनल प्रेस टाइम्स ब्लूरो

नागपुर। यह प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय मजदूर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल चौहान के नेतृत्व में उनके निवास पर पहुंचा और वहां ट्रक चालकों और मालिकों के खिलाफ हो रहे अमानवीय अत्याचारों और भ्रष्टाचार की समस्या को मंत्री के सामने रखा।

संघ के प्रतिनिधियों ने इस

दौरान ट्रक चालकों और मालिकों पर टोल और राज्य बॉर्डर क्रॉसिंग पर अधिकारियों

और उनके पाले हुए गुड़ों द्वारा

हो रहे उत्पीड़न को गंभीर

समस्याओं को उठाया। ट्रक

चालकों को शारीरिक और

मानसिक रूप से प्रतोड़ित किया

जाता है। संघ के प्रतिनिधि

मंडल में शब्दीरुल हसन, प्रमोद

चंचखड़े, जिंदेंद्र चौबे

किया जाए।

भ्रष्टाचार और गुंडागरी को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

ट्रक चालकों की सुरक्षा और समान सुनिश्चित किया जाए।

संघ ने उनसे मांग की कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि ट्रक चालक और मालिक अपने काम बिना भय और उत्पीड़न के लिए रोकने के साथ कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, तो वे सङ्कट

प्रतीक्षा करवाएं जाएं। केन्द्रीय मंत्री के लिए गुंडागरी को रोकने के लिए सख्त करवाई जाएगी।

यह बैठक में केंद्रीय मंत्री

नितिन गडकरी ने प्रतिनिधियों के अरोपणों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया एवं उन्होंने कहा कि

सङ्कट के साथ संघर्ष करने के लिए एक ट्रक चालकों और मालिकों के हितों की रक्षा

के लिए मजबूती देता है और वे इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

संघ की मांग:

टोल प्लाजा और राज्य बॉर्डर क्रॉसिंग पर अधिकारियों

द्वारा जो रही अवैध वसूली

पर रोक लगाई जाए। ट्रक

चालकों और मालिकों पर होने

वाले शारीरिक और मानसिक

अत्याचारों को तुरंत समाप्त

रक्षा के नाम पर बच्चों पर बोक (हड्डी) यानी उदारवादी राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही लैंगिक और नस्लीय मुद्दों पर भी इस विचारधारा का विरोध किया।

ट्रूप ने अपने प्रचार अभियान के दौरान कहा था कि वह स्कूलों को जल्द इस समर्थन का उम्मीदवार आवंटन देते हुए कहा कि इस

प्रूप द्वारा जो रही अवैध वसूली

पर रोक लगाई जाए। ट्रक

चालकों और मालिकों पर होने

वाले शारीरिक और मानसिक

अत्याचारों को तुरंत समाप्त

रक्षा के नाम पर बच्चों पर बोक (हड्डी) यानी उदारवादी राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही लैंगिक और नस्लीय मुद्दों पर भी इस विचारधारा का विरोध किया।

ट्रूप ने अपने प्रचार अभियान के दौरान कहा था कि वह स्कूलों को जल्द इस समर्थन का उम्मीदवार आवंटन देते हुए कहा कि इस

प्रूप द्वारा जो रही अवैध वसूली

पर रोक लगाई जाए। ट्रक

चालकों और मालिकों पर होने

वाले शारीरिक और मानसिक

अत्याचारों को तुरंत समाप्त

पेज एक का थोर...

कर्नाटक विधानसभा में बपाल, 18 विधायक छह महीने के लिए निलंबित

निलंबित विधायकों में ये हैं शामिल- निलंबित विधायकों में विपक्ष के मुख्य संचेतन डॉडुनगौड़ा एवं पाटिल, अस्वरथ नारायण सीएन, एसआर विश्वनाथ, बीए बसवराज, श्री एमआर पाटिल, चन्नबसप्पा (चन्नी), बी सुरेश गौड़ा, उमानाथ एवं कोट्यान, शरण सालगर, शैलेंद्र बेलडाले, सीके राममूर्ति, यशपाल एवं सुवर्ण, बीपी हरीश, रात शेष्टी वाई, मुनिराज, बसवराज मट्टीमूर्ति, धीरेंद्र शामिल हैं।

सदन से 18 भाजपा विधायकों के निलंबन को कर्नाटक सरकार में मंत्री एम.बी. पाटिल ने सही करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह से व्यवहार करना पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने विधानसभा में सभी संभव उल्लंघन किए एवं ऐसे में यह(निलंबन) 100% उचित है।

स्थगित हुई कार्यवाही

गौरतलब है कि विधानसभा में आज की कार्यवाही हांगमे की भेंट चढ़ गई। दिन भर हीनी ट्रैप और मुसलमान टेक्केदारों के लिए चार प्रतिशत आकर्षण के अराक्षण के मुद्दे हांगमा होता रहा। इस दौरान भाजपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और कुछ विधायकों ने अपने हाथों में सीढ़ी थामे हुई थी, जिन्हें लेकर दावा किया गया कि उनके पास नीली ट्रैप को ले लिया जाएगा। इसके बाद नीली ट्रैप को ले लिया जाएगा।

इसके बाद कुछ विधायकों ने नारेबाजी की और कुछ विधायकों

